भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 563
गुरूवार, 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

शहरी शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी को दूर करने हेतु कार्य योजना

563. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में बेरोजगार व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी/ग्रामीण/लिंग/शिक्षा के उच्चतम स्तर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शहरी शिक्षित महिलाओं में बढ़ती बेरोजगारी के विषय से अवगत है;

(ग) यदि हाँ, तो इसमें सुधार के लिए लागू किए गए किन्हीं अल्पकालिक उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार दीर्घकाल में शहरी शिक्षित महिलाओं हेतु रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाओं, कानूनों और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जाते हैं। 2019-20 की नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार/शहरी/ग्रामीण/लिंग/उच्चतम शैक्षिक स्तर की सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध- I, II, III, IV पर दी गई हैं।

(ख) से (घ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 27.11.2021 को 1.17 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.59 लाख लाभार्थियों जिसमें 10.13 लाख महिला लाभार्थी भी शामिल हैं को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना महिला लाभार्थियों से संबंधी 68% ऋण खातों के साथ महिलाओं को सशक्त बना रही है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी। पीएमकेवीवाई 2.0 योजना के तहत कुल रिपोर्टिंत नियोजन में से 52% महिलाएं थी।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

राज्य सभा के दिनांक 02.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 563 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

ग्रामीण **पुरूष** (प्रतिशत मे)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर				
	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक
आंध्र प्रदेश	2.7	7.5	21.5	22.4	47.4
अरुणाचल प्रदेश	9.3	9.9	0.0	20.9	62.1
असम	4.2	12.6	7.8	17.6	7.8
बिहार	4.3	6.6	97.7	19.7	14.3
छत्तीसगढ	1.6	5.8	74.6	14.9	15.8
दिल्ली	0.8	3.9	0.0	2.2	0.0
गोवा	2.2	8.3	9.2	10.3	0.0
गुजरात	2.0	2.7	1.8	12.7	14.1
हरियाणा	6.7	9.7	11.8	14.7	17.7
हिमाचल प्रदेश	1.5	5.4	13.2	19.6	7.3
झारखंड	6.4	8.2	0.0	14.9	19.1
कर्नाटक	3.9	4.5	16.6	10.5	18.0
केरल	6.0	18.3	13.7	20.7	14.2
मध्य प्रदेश	2.1	3.0	4.8	12.8	2.4
महाराष्ट्र	1.0	7.3	13.4	11.4	6.7
मणिपुर	4.4	13.4	0.0	18.5	22.9
मेघालय	2.4	4.0	0.0	14.1	0.0
मिजोरम	0.9	13.1	0.0	15.8	24.3
नागालैंड	24.4	32.1	0.0	46.7	74.8
ओडिशा	11.1	18.9	34.8	28.5	10.3
पंजाब	6.5	16.6	22.9	13.7	22.2
राजस्थान	3.7	2.5	8.3	22.0	12.1
सिक्किम	2.4	7.3	0.0	18.5	3.8
तमिलनाडु	4.4	8.9	20.4	29.0	10.2
तेलंगाना	4.2	11.5	5.3	29.4	35.4
त्रिपुरा	5.6	6.7	1.9	17.1	8.1
उत्तराखंड	5.8	17.6	12.7	18.4	4.8
उत्तर प्रदेश	3.1	5.9	11.5	13.5	4.8
पश्चिम बंगाल	7.1	11.4	11.3	23.5	18.7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.8	35.9	22.6	6.3	0.0
चंडीगढ़	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
दादर और नगर हवेली	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	16.4	0.0	18.6	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1.6	9.8	58.3	14.9	7.9
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	0.0	18.2	5.3	9.7	8.4
अखिल भारत	**4.2**	**7.9**	**16.5**	**18.1**	**13.6**

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

राज्य सभा के दिनांक 02.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 563 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

ग्रामीण **महिला** (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर				
	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक
आंध्र प्रदेश	2.5	5.6	9.9	46.9	57.5
अरुणाचल प्रदेश	18.2	24.7	0.0	48.3	14.7
असम	28.0	27.8	0.0	30.3	6.8
बिहार	0.0	2.0	0.0	13.2	0.0
छत्तीसगढ	0.0	8.2	0.0	27.8	12.4
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गोवा	5.8	57.6	0.0	43.4	17.3
गुजरात	0.0	0.4	0.0	1.6	4.4
हरियाणा	3.1	14.1	0.0	30.2	8.8
हिमाचल प्रदेश	0.1	2.1	9.3	16.3	12.7
झारखंड	0.0	6.4	0.0	1.3	0.0
कर्नाटक	1.5	3.9	26.7	29.0	15.1
केरल	6.9	26.7	10.0	43.1	36.9
मध्य प्रदेश	0.0	3.2	0.0	15.7	8.8
महाराष्ट्र	1.6	4.7	35.6	16.8	0.5
मणिपुर	23.3	15.0	0.0	19.2	16.1
मेघालय	3.1	12.1	0.0	14.3	8.6
मिजोरम	0.0	15.9	0.0	19.3	0.0
नागालैंड	39.0	62.0	0.0	63.5	68.3
ओडिशा	11.3	22.0	0.0	35.5	4.9
पंजाब	0.3	23.5	0.0	34.6	13.3
राजस्थान	0.4	0.0	0.0	35.6	36.9
सिक्किम	0.0	5.0	80.3	5.1	0.0
तमिलनाडु	0.9	6.9	14.8	33.4	49.0
तेलंगाना	2.1	3.7	0.0	62.4	23.1
त्रिपुरा	1.8	11.1	100.0	19.1	3.3
उत्तराखंड	0.0	8.0	100.0	37.1	1.9
उत्तर प्रदेश	1.3	0.1	100.0	20.0	11.1
पश्चिम बंगाल	6.3	5.4	5.7	20.3	18.8
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	77.9	27.3	32.5	60.7	6.5
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दादर और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	14.8	25.6	93.8	36.9	41.7
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	44.7	0.0	0.0	100.0	0.0
पुडुचेरी	4.3	1.5	74.4	44.6	0.0
अखिल भारत	**3.1**	**7.9**	**15.2**	**29.9**	**24.0**

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

राज्य सभा के दिनांक 02.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 563 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

शहरी **पुरूष** (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर				
	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक
आंध्र प्रदेश	4.6	5.7	12.2	19.8	8.3
अरुणाचल प्रदेश	6.9	3.5	0.0	18.1	23.6
असम	7.7	7.6	0.0	13.8	6.6
बिहार	2.1	7.6	57.7	21.3	5.1
छत्तीसगढ	7.1	7.1	9.0	15.6	7.4
दिल्ली	6.2	9.4	18.7	14.0	17.3
गोवा	5.4	7.2	22.9	11.9	11.4
गुजरात	1.8	5.1	7.8	2.3	3.2
हरियाणा	5.6	11.6	18.6	8.1	4.2
हिमाचल प्रदेश	0.0	8.6	4.7	7.4	8.9
झारखंड	9.9	13.1	29.0	11.6	11.2
कर्नाटक	2.3	2.7	5.0	9.2	5.2
केरल	6.7	12.4	11.0	20.2	8.1
मध्य प्रदेश	4.6	8.0	15.8	14.8	5.7
महाराष्ट्र	4.6	4.5	5.2	6.0	1.2
मणिपुर	5.1	10.8	58.6	18.9	19.9
मेघालय	7.8	7.2	0.0	14.2	30.0
मिजोरम	5.0	9.6	0.0	10.9	22.7
नागालैंड	18.3	18.7	48.5	37.3	52.4
ओडिशा	8.5	9.1	19.9	13.3	7.6
पंजाब	3.8	12.3	13.1	12.1	4.8
राजस्थान	2.3	10.9	33.4	21.6	12.1
सिक्किम	2.9	2.5	0.0	7.6	3.9
तमिलनाडु	3.1	3.6	12.1	14.0	6.5
तेलंगाना	6.8	8.4	10.5	18.9	17.8
त्रिपुरा	3.0	5.5	93.4	6.7	0.0
उत्तराखंड	2.7	6.1	26.7	19.2	8.7
उत्तर प्रदेश	5.2	9.8	16.9	17.5	10.1
पश्चिम बंगाल	3.3	6.9	16.3	8.6	4.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.5	10.7	3.6	20.7	2.1
चंडीगढ़	8.0	9.4	0.0	4.1	5.3
दादर और नगर हवेली	4.7	0.0	3.3	12.5	23.0
दमन और दीव	0.1	10.6	0.0	5.9	0.0
जम्मू और कश्मीर	4.0	12.8	18.9	13.1	10.8
लद्दाख	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	2.8	22.8	31.2	15.3	0.0
पुडुचेरी	2.8	4.0	7.0	18.0	0.0
अखिल भारत	**4.4**	**7.5**	**10.8**	**12.7**	**7.9**

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

राज्य सभा के दिनांक 02.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 563 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

शहरी **महिला** (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर				
	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक
आंध्र प्रदेश	4.5	16.2	13.4	29.3	25.8
अरुणाचल प्रदेश	1.0	6.4	0.0	23.0	28.5
असम	19.9	30.2	0.0	32.6	5.9
बिहार	0.0	0.0	100.0	26.8	31.5
छत्तीसगढ	1.5	9.6	0.0	24.5	17.1
दिल्ली	0.0	17.5	0.0	11.7	13.6
गोवा	34.8	6.9	5.9	16.8	25.4
गुजरात	0.5	4.8	4.0	6.8	17.4
हरियाणा	0.0	10.5	8.7	23.5	7.5
हिमाचल प्रदेश	0.0	7.8	0.0	32.0	17.6
झारखंड	12.8	4.9	0.0	35.4	18.8
कर्नाटक	1.5	0.9	3.9	43.3	11.9
केरल	7.4	15.4	24.1	33.7	36.1
मध्य प्रदेश	4.1	3.4	42.8	19.8	10.4
महाराष्ट्र	4.7	10.5	14.0	9.7	2.2
मणिपुर	5.4	12.4	0.0	13.8	25.1
मेघालय	5.0	38.5	42.1	28.3	25.5
मिजोरम	4.4	16.7	0.0	18.2	21.7
नागालैंड	25.5	23.1	0.0	46.8	34.4
ओडिशा	7.9	6.1	57.3	25.6	17.6
पंजाब	6.7	19.6	9.4	13.7	24.0
राजस्थान	2.3	19.7	0.0	14.6	26.0
सिक्किम	0.0	2.2	0.0	10.2	0.0
तमिलनाडु	1.5	5.4	20.9	18.9	15.0
तेलंगाना	2.9	22.4	55.8	25.0	38.6
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	15.1	14.3
उत्तराखंड	16.3	18.5	100.0	19.3	20.1
उत्तर प्रदेश	3.3	10.6	8.0	21.0	24.7
पश्चिम बंगाल	1.5	5.9	27.8	15.2	11.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39.1	66.2	33.0	32.1	52.6
चंडीगढ़	15.3	17.6	0.0	0.0	15.3
दादर और नगर हवेली	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	33.1	38.2	25.2	44.9	44.8
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	12.8	66.7	23.8	20.7	0.0
पुडुचेरी	6.4	21.0	0.0	20.5	23.1
अखिल भारत	**4.1**	**10.5**	**18.3**	**21.7**	**17.3**

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।